जनमानस ने मन बनाया, प.बंगाल में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी में कहा कि बंगाल की जनता तृष्टिकरण व भ्रष्टाचार से त्रस्त है

सिलीगुड़ी/जयपुर, 17 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। ममता जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास अवरूद्ध हो गया है, सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है तथा घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, भाजपा का संकल्प है, साफ नीयत, स्पष्ट नीति और तेज गति से विकास। पश्चिम बंगाल में जनमानस ने भाजपा के पक्ष में मन बना लिया है और यहां भाजपा की सरकार भारी बहुमत से जीतेगी। शर्मा शुक्रवार को पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित मारवाड़ी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

- मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी में मारवाड़ी समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के पक्ष में रोड शो में भाग लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में आयोजित भव्य रोड शो में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी देश और दुनिया में राजस्थान की संस्कृति और परम्परा को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मारवाड़ी लोगों को अपने परोपकारी कार्यों के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है। प्रवासी राजस्थानी केवल आर्थिक गतिविधियाँ ही नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज ने कर्मभूमि में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाएं, गौशाला और देवालय बनवाकर सेवा भाव का परिचय दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत 520 किमी लंबा गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बन रहा है, जिससे अब यूपी से बंगाल की दूरी घंटों में सिमट जाएगी। साथ ही, कोलकाता-सिलीगुड़ी के बीच 6-लेन हाईवे और बागडोगरा एयरपोर्ट का नया आधुनिक टर्मिनल यहां के व्यापार और पर्यटन की तस्वीर बदल देगा।

मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में आयोजित भव्य रोड शो में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर आमजन का अभिवादन स्वीकार किया। शर्मा का विभिन्न स्थानों पर लोगों ने फूल-मालाओं से अभिनंदन किया। 'भारत माता की जय' 'जय श्री राम' और भाजपा के समर्थन में लगे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे।

हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये

लखनऊ, 17 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश ने कांग्रेस सांसद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर यह मामला गरमा गया है। कोर्ट में दायर अर्जी में गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल, राहुल गांधी के रायबरेली से सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रखने का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं।

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

ईरान से भारत ने 2361 लोगों को सुरक्षित निकाला

विदेश मंत्रालय ने बताया इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका व गुयाना का एक-एक नागरिक भी शामिल है

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक, ईरान से अपने एवं मित्र देशों के 2361 नागरिकों को आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते से सुरक्षित निकाला है।

- विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में अभी भी 6 से 7 हजार भारतीय मौजूद हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, "संघर्ष के प्रकोप के बाद से हमने 2,361 नागरिकों को ईरान से सुरक्षित रूप से निकालने में मदद की है। इनमें से 2,060 आर्मेनिया के माध्यम से और 301 अज़रबैजान के माध्यम से आए हैं। इन 2,361 लोगों में 1,041 भारतीय छात्रों के साथ तीन विदेशी भी शामिल हैं। एक बांग्लादेश से, एक श्रीलंका से और एक गुयाना से है।"

उन्होंने कहा कि ईरान में अभी भी 6000 से 7000 भारतीय मौजूद हैं। पश्चिम एशिया संकट पर एक अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन ने भी कहा, "सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में निगरानी करना जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय में एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष परिचालन कर रहा है और हमारे मिशनों के साथ समन्वय में काम कर रहा है। स्थानीय सरकार के दिशानिर्देशों, उड़ान और यात्रा की स्थिति, कांसुलर सेवाओं और हमारे समुदाय का समर्थन करने के लिए किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों से संबंधित जानकारी के साथ अपडेटेड सलाह जारी की जा रही है।"

महाजन ने कहा कि इस क्षेत्र से भारत के लिए उन देशों से उड़ानें जारी हैं, जहां हवाई क्षेत्र खुला है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अब तक ईरान से आर्मेनिया और अज़रबैजान तक 2,358 भारतीय नागरिकों की भारत की आगे की यात्रा के लिए आवाजाही की सुविधा प्रदान की है। इज़राइल का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से प्रतिबंधित उड़ान संचालन के साथ खुला है। हम जॉर्डन और मिस्र के माध्यम से इज़रायल से भारतीय नागरिकों की यात्रा को भारत तक सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

खंडपीठ ने वेटनरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में कहा गया कि आरपीएससी ने गत 17 जुलाई को वेटनरी ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई, जो पाठ्यक्रम के अंतिम साल में थे या इंटर्नशिप कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने 19 अप्रैल, 2026 को भर्ती परीक्षा तय की है, लेकिन उस समय तक उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है। पशुपालन विभाग ने भी गत 9 जनवरी को परीक्षा तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी हस्तक्षेप किया गया, लेकिन आयोग ने तिथि नहीं बढ़ाई। इसके अलावा, पशुपालन विवि ने भी आयोग को पत्र लिखकर इंटर्नशिप में देरी के कई कारण बताए थे। ऐसे में परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। इसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और सभी बीस परीक्षा केन्द्रों पर सारी तैयारी कर ली गई है।

यदि परीक्षा टाली गई तो चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट की एकलपीठ भी परीक्षा तिथि में बदलाव से इनकार कर चुकी है। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने परीक्षा तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

रूस से तेल खरीदने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महीनों में रूस भारत के लिए तेल का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा, लेकिन व्यापार करने का तरीका बदल सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिफाइनरी कंपनियां आने वाले महीनों में सीधे प्रतिबंधित रूसी फर्मों से डील करने से बचेंगी और इसके बजाय, व्यापार मध्यस्थों का उपयोग करना पसंद करेंगी। साथ ही, भारत शिपिंग और भुगतान के लिए कड़ी अनुपालन जांच का पालन करेगा।

अमेरिकी छूट का उद्देश्य खाड़ी संकट के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति में अचानक व्यवधान को रोकना था। इस छूट ने सुनिश्चित किया कि कट-ऑफ तिथि से पहले समुद्र में भेजा गया कच्चा तेल अभी भी खरीदारों तक पहुँच सके। इससे वैश्विक बाजार स्थिर रहने में मदद मिली। भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं की ओर अधिक आकर्षित हुईं, क्योंकि उन्होंने कम कीमत और बड़ी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध कराया।

वैश्विक तेल बाजार भू-राजनीतिक तनाव, कुछ क्षेत्रों में शिपिंग जोखिम और सप्लाई चेन में व्यवधान के कारण, कीमत के मामले में संवेदनशील बना हुआ है। इसलिए, भारत कम से कम कुछ समय रूसी तेल की खरीद जारी रख सकता है, हालांकि व्यापार का तरीका अधिक जटिल होने की और सतर्क निगरानी रहने की संभावना है।

विदेश मंत्रालय शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की समीक्षा कर रहा है

साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता ने कहा कि समीक्षा में न्यायिक व आंतरिक कानूनी प्रक्रियायें शामिल हैं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इससे जुड़ी एक याचिका की समीक्षा की जा रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में शेख हसीना के मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में एक अनुरोध विचाराधीन है, जो चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा है। भारत इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से संवाद जारी रखेगा और हर स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव की भारत की इच्छा दोहराई है और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है।

दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से प्रस्तावों पर विचार करने पर सहमति जताई है। वहीं,

- प्रवक्ता ने बताया कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर भारत ब्रिटेन से लगातार संपर्क में है।

देश के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़े प्रश्न पर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले में ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है। इस विषय में कानूनी प्रक्रिया जारी है और भारत सरकार इस पर करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्पष्ट नीति है कि देश से भागे हुए आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संबंधित देशों के साथ समन्वय के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपने की मांग की थी।

ट्रंप ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्रंप के बयान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका मध्य पूर्व में कई कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ा रहा है, जिसमें ईरान के साथ बातचीत और इज़रायल-लेबनान सीमा पर तनाव रोकने की कोशिशें शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि हिज़बुल्लाह के मामले में लेबनान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे हिज़बुल्लाह का ध्यान रखेंगे... वे अभी हिज़बुल्लाह पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो वह मिडिल ईस्ट की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा... सही समय पर।" इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका का कूटनीतिक दायरा दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व तक बढ़ रहा है, और वह ईरान और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रगति चाहता है।

होर्मुज़ खुलने से तेल की कीमत 10 प्रतिशत घटी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, ईरान द्वारा होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने की घोषणा के बाद शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस कदम से फारस की खाड़ी से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जिससे दुनिया भर में ग्राहकों तक कच्चे तेल की आपूर्ति सुचारू हो सकेगी। कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल होने और भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद के बीच अमेरिकी शेयर बाजार एक और रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ गए हैं।

- बैंच मार्क माने जाने वाले अमेरिकी क्रूड की कीमत 81.28 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थिति से बचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर ऊर्जा बाजार पर दिखा है।

''डोन्ट डू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए? महिला आरक्षण तैयार है... इसे परिसीमन से जोड़ना भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को हमारे देश के सबसे विवादास्पद और जटिल प्रशासनिक कवायद में बंधक बनाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनका आरक्षण देने का समर्थन करती है।

थरूर ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया से उन राज्यों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया है और जिन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सरकार से कहा, "कोई भी परिसीमन प्रक्रिया जटिलताओं से भरी होती है, जो हमारे संघवाद के मूल ताने-बाने को नुकसान पहुँचा सकती है।

परिसीमन प्रक्रिया पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इसे जल्दीबाज़ी में नहीं किया जा सकता। महिला आरक्षण बिल आज पारित करें, हम उसका समर्थन करेंगे। जहाँ तक परिसीमन का प्रश्न है, इसे टाल दें। महिलाओं को उनका आरक्षण दें, कृपया देश के बड़े हित पर विचार करें।

कोलकाता में तृणमूल नेताओं पर ईडी व इनकम टैक्स की रेड

ईडी व इनकम टैक्स की टीमों ने शुक्रवार सुबह से ही अलग-अलग स्थानों पर रेड की

कोलकाता, 17 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाही लगातार जारी है। जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक रियल एस्टेट कंपनी और एक निर्माण संस्था के ठिकानों पर छापेमारी की, वहीं आयकर विभाग की तरफ से रासबिहारी के तृणमूल उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई। शुक्रवार सुबह सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ईडी की कई टीमें पहुंचीं। उनके साथ केन्द्रीय बल भी थे।

ईडी की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह से ही एक रियल एस्टेट कंपनी के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी के अधिकारी साल्ट लेक और कोलकाता में चार जगहों पर पहुंचे हैं। उन्होंने न

- रासबिहारी के तृणमूल प्रत्याशी देबाशीष कुमार के घर इनकम टैक्स की रेड हुई वहीं एक रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी ने छापेमारी की।

केवल रियल एस्टेट कंपनी, बल्कि एक अन्य निर्माण कंपनी के कार्यालय पर भी छापेमारी की।

सूत्रों के मुताबिक, ये सर्च ऑपरेशन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले को लेकर है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े घरों, फ्लैटों और दफ्तरों में तलाशी अभियान चलाया गया था। ईडी ने दावा किया कि यह ऑपरेशन चुनाव से पहले अवैध वित्तीय लेनदेन को रोकने और कुछ भूमि संबंधी मामलों में लेनदेन की जानकारी खोजने के लिए था।

दूसरी ओर, ईडी के अलावा एक अन्य केन्द्रीय एजेंसी आयकर विभाग भी कोलकाता में तलाशी अभियान चला रहा है। उन्होंने शुक्रवार सुबह रासबिहारी निर्वाचन क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर सहित कई स्थानों पर दबिश दी।

आयकर विभाग की एक टीम शुक्रवार सुबह रासबिहारी के निवर्तमान विधायक देबाशीष के मनोहरपुकुर रोड स्थित घर पहुंची। न सिर्फ उनके घर, बल्कि मनोहरपुकुर रोड स्थित उनके चुनाव कार्यालय पर भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा था।

'एक माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की एकलपीठ ने यह आदेश सुंदरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ साल 2023 में तय कर चुकी है कि बहू भी बेटी के समान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, तो यह जानते हुए भी विभाग की ओर से जवाब में वही आपत्ति उठाई गई है, जिसे पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति की भी छह साल पूर्व मौत हो चुकी है। ऐसे में परिवार के सभी आश्रित याचिकाकर्ता पर ही निर्भर हैं।

याचिका में अधिवक्ता आरसी गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के ससुर सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदस्थापित थे। इस दौरान 19 नवंबर, 2016 को उनकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता के पति का पिता के जीवनकाल में ही एक्सीडेंट हो गया था और वह पूरी तरह से बेड पर आ गया था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने उस पर विचार नहीं किया। मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्ति देते हुए, पालना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।

ईरान में 48 दिन बाद गूगल सर्च सेवा बहाल

ईरान ने युद्ध शुरु होने पर इंटरनैट बंद कर दिया था उसमें अब आंशिक राहत देनी शुरु कर दी है

तेहरान, 17 अप्रैल। ईरान में करीब 48 दिनों तक चले इंटरनेट प्रतिबंधों के बाद आंशिक अब राहत मिली है। देश में अब गूगल सर्च सेवा बहाल कर दी गई है, जिससे आम नागरिक फिक्स्ड लाइन और मोबाइल इंटरनेट के जरिए सर्च इंजन का उपयोग कर पा रहे हैं। हालांकि, इंटरनेट कनेक्टिविटी अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकी है और कई जगहों पर उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां एक ओर गूगल सर्च की वापसी हुई है, वहीं जीमेल समेत, कई अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं अब भी बंद हैं। इससे स्पष्ट है कि देश में इंटरनेट सेवाएं अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई हैं और डिजिटल गतिविधियों पर आंशिक

- अभी भी जीमेल सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं बंद हैं और इंटरनैट कनैक्टिविटी भी अस्थिर है।

प्रतिबंध जारी है।

अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य संघर्ष के बाद ईरानी सरकार ने देश में इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। इस दौरान आम नागरिकों के लिए इंटरनेट एक्सेस लगभग बंद कर दिया गया था। केवल कुछ सीमित यूजर्स, जैसे सरकारी नेटवर्क से जुड़े लोग या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल करने वाले-ही इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे थे।

लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इन पाबंदियों के चलते ईरान को करीब 1.8 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। ई-कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं और छोटे व्यवसायों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सरकार की ओर से इंटरनेट सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी सेवाएं पूरी तरह कब तक सामान्य हो पाएंगी। फिलहाल, आंशिक बहाली को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन पूर्ण डिजिटल सामान्य स्थिति बहाल होने में अभी समय लग सकता है।

'15 अप्रैल को हमने आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अदालत को गुमराह किया गया। मैंने एक छोटा सा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज दाखिल किया, और कोर्ट का यह अवलोकन अग्रिम जमानत पर निर्णय लेने वाली किसी भी अदालत को बाध्य नहीं करेगा।

बैंच ने टिप्पणी की, "छोटी गलती? आप जाली और फैब्रिकेटेड दस्तावेज़ दाखिल नहीं कर सकते। और हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि असम पुलिस ने अदालत को गुमराह कर आदेश लिया है।"

बैंच ने दोहराया कि जब किसी सक्षम अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है, तो इसे ट्रांज़िट जमानत देने या उसे रोकने के आदेश से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

असम पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खेड़ा की अग्रिम जमानत को बढ़ाने के प्रयास का विरोध किया। मेहता ने कहा कि खेड़ा को असम में जिला अदालत जाने से कोई नहीं रोक रहा, जो शुक्रवार को खुली है।

असम पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, यह कहते हुए कि खेड़ा "जाली" दस्तावेज़ों के आधार पर उच्च न्यायालय गये। पुलिस ने कहा कि कथित अपराध, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां खेड़ा ने आरोप लगाए, असम में हुई और मामला असम में दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने कहा कि खेड़ा के आधार कार्ड पर उनका दिल्ली का पता दर्ज था।

खेड़ा ने तर्क दिया कि उनकी पत्नी हैदराबाद की निवासी हैं और वहां विधानसभा चुनाव लड़ी थीं। "यह मूल रूप से मानहानि का मामला है, और सिर्फ इसलिए कि मैंने मुख्यमंत्री को नाराज़ किया, 100 पुलिसकर्मी दिल्ली भेज दिए गए।"

असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और पवन खेड़ा के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब खेड़ा ने प्रेस से हुई बातचीत में सन्दर्भित टिप्पणी की।

उन्होंने दावा किया कि सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन सक्रिय विदेशी पासपोर्ट हैं और अमेरिका में कई अघोषित संपत्तियां हैं।

इसके बाद, सरमा ने एफआईआर दर्ज कराई और अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। असम पुलिस ने उनके दिल्ली घर पर छापा मारा, लेकिन उस समय वे दिल्ली से बाहर थे।

खेड़ा ने असम की उचित अदालत तक पहुँचने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में ट्रांज़िट अग्रिम जमानत का आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने उन्हें अस्थायी राहत दी, जिससे उन्हें सीमित सुरक्षा मिली, और विधिवत जमानत के लिए असम की क्षेत्राधिकार वाली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया।

हिमंता सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के ट्रांज़िट जमानत आदेश पर स्टेट दे दिया।

ईरान ने अचानक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के इंतजाम पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि, इस व्यवस्था की निगरानी करने में उनकी क्षमता पर संदेह जताया जा रहा है। लेकिन पहले कदम उठाने की चमक और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के ध्यान से चूक गए ट्रंप ने अपने तरीके से घोषणा की कि ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर अमेरिकन ब्लॉकेड फिलहाल जारी रहेगा। इस प्रकार ट्रंप ने खेल बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाई, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान की अचानक घोषणा ने उन्हें चतुराई से मात दे दी।

डॉनल्ड ट्रंप के अस्थिर तरीकों को देखते हुए, कोई भी निश्चित रुप से नहीं कह सकता है कि वह ब्लॉकेड को हटाने या होर्मुज़ जल में पीछे हटने की घोषणा कब करेंगे। ब्लॉकेड की नीति जारी रखने से अमेरिका शेष विश्व, खासकर चीन, को परेशान कर रहा है।

चीन ईरान से तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और अब इसे असर महसूस हो रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि जब ईरानी कच्चे तेल से भरा कोई जहाज चीन के बंदरगाह के लिए जाएगा और अमेरिकी ब्लाकेड से टकराएगा, तो क्या अमेरिकी नौसेना उसे वापस लौटने के लिए बाध्य करेगी या उसे बोर्डिंग और तलाशी के लिए रोक देगी।

संकेत हैं कि ईरान-अमेरिका शांति वार्ता जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है। बेहतर संभावनाओं को देखते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वे स्वयं पाकिस्तान यात्रा करेंगे, ताकि शांति समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके। लेकिन संकेत हैं कि युद्ध क्षेत्र में राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

'चाणक्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे हैं। वे मेरी बात से सहमत हैं।" चाणक्य वाले कमेंट पर गृह मंत्री मुस्कुराए और कोई नाराज़गी नहीं दिखाई दी।

महिला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्योंकि ओबीसी और अन्य वर्गों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है, जो अब तक नहीं हुआ।

नरेन्द्र मोदी और अमित शाह चूँकि हार गए हैं, इसलिये अब वे यह कथित कहानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है और असल में केवल भाजपा ही महिलाओं की हितैषी है।

तीन दिन का विशेष सत्र भाजपा ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए बुलाया था, लेकिन बिल के बहाने सरकार इसे परिसीमन से जोड़ रही है, सीटों को 850 तक बढ़ा रही है और वह भी बिना जनगणना के।

परिणाम अपेक्षित था।

घटना की दिशा तय हो चुकी है।

यह भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के अंत की शुरुआत है।

विपक्ष को तोड़ने के प्रयास विफल रहे और भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का समय है, सही और गलत की पहचान करने का समय है।

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक को उम्रकैद की सज़ा

बंगलूरू, 17 अप्रैल। कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में सजा की अवधि (क्वांटम ऑफ सेंटेंस) को लेकर बंगलूरू की एमएलए/एमपी विशेष अदालत ने विनय कुलकर्णी समेत 16 दोषियों को हत्या और साजिश के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने उन पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

- भाजपा नेता योगेश गौडा की हत्या के मामले में अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी सहित 16 को उम्रकैद की सजा सुनाई।

बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि सभा की विशेष अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी पाए गए कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और अन्य आरोपियों को सजा सुनाई।

विनय कुलकर्णी पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

अदालत में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और दोषी कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के वकीलों की अंतिम दलीलें पूरी हो गईं। इसके बाद न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले को स्थगित करते हुए फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की तारीख तय की थी। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में भावुक माहौल देखने को मिला। दोषियों के परिजन बड़ी संख्या में मौजूद थे और कई लोग रोते हुए नजर आए। कुछ दोषी, जिनमें विधायक विनय कुलकर्णी भी शामिल हैं, अपने परिजनों को सांत्वना देते दिखे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600